



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1743]
No. 1743]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2705(अ).—यतः मै. डीएलएफ लिमिटेड ने प्लॉट सं. टीपी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राई, सोनीपत, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2097(अ) दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा प्लॉट सं. टीपी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राई, सोनीपत, हरियाणा में 10.2498 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र अधिसूचित किया है;

और यतः डीएलएफ लिमिटेड, ने प्लॉट सं. टीपी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राई, सोनीपत, हरियाणा में 10.2498 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव भी किया है और केन्द्र सरकार ने 5 जून, 2009 को अनधिसूचित करने हेतु अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में 22 अगस्त, 2008 को सं. का.आ. 2097(अ) दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना को निरस्त करती है, सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/603/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2705(E).—Whereas M/s. DLF Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonapat in the State of Haryana;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, has notified the total area of 10.2498 hectares at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonapat in the State of Haryana as Special Economic Zone in the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 2097(E), dated 22nd August, 2008;

And whereas M/s. DLF Limited has proposed to de-notify an area of 10.2498 hectares at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonapat in the State of Haryana and the Central Government has granted letter of approval for denotification at Haryana on 5th June, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) dated 22nd day of August, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 2097(E) dated the 22nd August, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/603/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.